News item/letter/article/editorial published on January 18.1.2017 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

H 18

SC asks govt. to file status report on Ganga rejuvenation

Details sought on construction, functioning of sewage treatment plants alongside river

LEGAL CORRESPONDENT

The Ganga being cleaned during the 2016 Ardh Kumbh Mela in Haridwar. — FILE PHOTO: PTI

NEW DELHI: Almost two years after the Supreme Court voiced scepticism about the government's self-proclaimed promise to clean up the Ganga river, the court on Tuesday sought a fresh status report from the Centre on what it was doing to revive the holy river.

The report was sought on a 32-year-old pending public interest litigation petition filed by environmental lawyer, M.C. Mehta.

In 2014, the Supreme Court voiced its scepticism about the various efforts over the decades to return the Ganga to its pristine self, once even saying that it "does not expect Ganga to be cleaned up even after 200 years."

In a hearing on Mr. Mehta's PIL filed in 1985, a Bench led by Chief Justice of India J.S. Khehar directed the government to file a report on the construction and functioning of sewage treatment plants alongside the river, which runs through five States.

The court wants the report by Tuesday next.

In 2014, the Supreme Court said that its "last hope" rested on the National Green Tribunal (NGT) and referred the task of monitoring industrial units along the Ganga to the NGT.

The court had even empowered the tribunal to cut off water and power connections if the units are found to be polluting the river.

The court had observed that official apathy coupled with "failure at various levels" in both the State and the Central Pollution Control Board had led to the Ganga dying at the hands of "highly" and "grossly" polluting units, which flushed their untreated effluents into the river without any checks.

IITs' consortium

In January 2015, the government had informed the Supreme Court that a consortium of IITs was preparing a road map to rejuvenate the river.

It informed that a proposal is on track to have a total of 80 sewage treatment plants (STPs) which would process, in a day, 368 million litres of water flowing into the river in the five river basin States.

In March 2015, the government submitted a detailed report prepared by the IITs for the revival of the river to its former "wholesome" self.

The Ganga River Basin Management Plan (GRBMP) 2015 drafted by the IIT consortium had pointed to several problems, from rapid urbanisation to over-grazing, which has led to the slow destruction of the river.

News item/letter/article/editorial published on January 18, 2017 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

पत्रिका - 18-1-17

तालाब बने कमाई की खान...

सालाना खर्च 10 करोड़ रुपए, फिर भी बीमार हैं शहर के सभी तालाब

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. साल-दर-साल खत्म हो रहे तालाबों को देखकर राजधानीवासी भले ही दुखी हो रहे हो, लेकिन नगर निगम अफसरों के लिए ये तगड़ी कमाई का जरिया बन चुके हैं। निगम ने तालाबों को सहेजने और इनके सौंदर्यीकरण के नाम पर बीते सालों में जमकर चांदी काटी है। सूचना के अधिकार के तहत 2012 से अब तक का खर्च ही चौंकाने वाला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हर साल दस करोड़ रुपए तालाबों के संरक्षण के नाम पर खर्च किए जाते हैं। 2012 से अब तक करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अपने अस्तित्व के अंतिम सांसें भर रहे तालाबों के नाम भी लाखों रुपए निकाल लिए गए। तालाबों के नाम पर बीते चार साल में खर्च की तमाम राशि की जानकारी पत्रिका के पास है।

इन कामों का दावा

प्रकाश व्यवस्था, फ्लोटिंग फाउंटेन, बाउंड्रीवॉल मरम्मत, गार्डन लाइट, किनारों का सौंदर्यीकरण, पार्क, पाथवे, सीवेज पंप, पूजन सामग्री कुंड, मुनारे, रिटेनिंग वॉल-प्लेटफार्म, मूर्ति विसर्जन घाट आदि।

जहर जैसा है पानी

बड़ा तालाब के पानी को लेकर एप्को की जून 2016 में आई रिपोर्ट के अनुसार कोहेफिजा में शिरीन नदी के पास तालाब का पानी 14 गुना तक प्रदूषित है। यहां केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) का प्रतिशत 10 के मुकाबले 144 मिला है। बायो ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) भी 9 गुना तक ज्यादा है। छोटा तालाब में बीओडी 203 सीओडी है। शाहपुरा में भी सीओडी 313 आई है। एप्को से इनकी जांच कराई गई थी।

जिम्मेदार से सीधी बात

मलिका निगम, अपर आयुक्त

Q. तालाबों के नाम हर साल करोड़ों खर्च हो रहे, इसकी कोई समीक्षा की है?

A. समीक्षा करते रहते हैं, पर मैं अक्टूबर में आई हूं और उसके बाद से कोई बड़ी राशि खर्च नहीं हुई।

Q. आपके आने से पहले जो खर्च हुई है उसका कितना लाभ मिला, इस तरह की कोई पहले समीक्षा की गई हो?

A. नहीं इस तरह की समीक्षा तो मेरे पास नहीं है।

Q. समीक्षा नहीं होगी तो खर्च सही हुआ या गलत कैसे पता चलेगा?

A. मैं इसकी पूरी समीक्षा करूंगी और जो खर्च हुआ है उसे जरूर जस्टिफाइड कराया जाएगा।

ऐसे खर्च किए करोड़ों

वर्ष 2012-2013 में

बड़ा तालाब :	38.38
छोटा तालाब :	29.96
हथाईखेड़ा बांध :	09.13
बागमुंशी खां तालाब :	1.98

वर्ष 2013-14

बड़ा तालाब :	1,85,85803
छोटा तालाब :	1,25,27565
शाहपुरा तालाब :	9,96,860

वर्ष 2014-15

बड़ा तालाब :	25,44,7683
छोटा तालाब:	1,45,77,228
शाहपुरा तालाब :	88,78,962
मोतिया, बागमुंशी, सिद्दीक व अन्य तालाब :	36.57 लाख

वर्ष 2015-16

बड़ा तालाब :	54.58 लाख
छोटा तालाब :	21.25 लाख
मोतिया तालाब :	10.89 लाख
अन्य तालाबों पर :	5 करोड़ खर्च किए गए

News item/letter/article/editorial published on January 18 2017 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi) ✓	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

गंगा की सफाई पर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गंगा की सफाई पर केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अगले मंगलवार तक गंगा किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए उठाए कदमों के बारे में रिपोर्ट का निर्देश दिया है।